

## बजिली खरीद प्रथाओं में सुधार की आवश्यकता

### संदर्भ

भारत में बजिली के खुदरा टैरिफों पर हमेशा चर्चा जताई जाती है, लेकिन वडिंबनात्मक रूप से उन घटकों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जो कुल लागत को बढ़ाने में अहम योगदान देते हैं। बजिली उत्पादन की लागत इसकी सप्लाई लागत की 70-80% होती है और बजिली खरीद प्रथाओं का इस लागत पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फरि भी इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि भी डस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डस्टिकॉम) किस प्रकार बजिली की खरीदारी करती हैं।

### प्रमुख बट्टि

- थर्मल वदियुत सयंत्रों में कम होते प्लांट लोड फैक्टर (PLFs) इस बात का सूचक हैं कि कुछ राज्यों के पास अधिशेष बजिली पैदा करने की क्षमता है।
- कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अधिशेष क्षमता लगातार कमी से बेहतर है, लेकिन कमी से अधिशेष की ओर बदलाव डस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा खरीद प्रथाओं में गंभीर खामियों को भी इंगति करता है।
- वर्तमान प्रथाएँ अल्पकालिक रूप से संसाधन पर्याप्तता सुनिश्चित करने और चरम मांग की स्थिति में आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। लेकिन संसाधन पर्याप्तता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है, इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है।
- डस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को कम से कम लागत में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संसाधनों का समझदारीपूर्वक उपयोग करना चाहिये।
- अतः वचिर-वमिर्श को केवल संसाधन पर्याप्तता पर केंद्रित रखने के बजाय संसाधन नयोजन (resource planning) की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। संसाधनों संबंधी प्लानिंग सामान्यतः 10-20 वर्ष के लयि की जाती है।
- दुरभाग्यवश, संसाधन नयोजन भारतीय वदियुत सेक्टर के प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है और न ही इसे कभी अधिक महत्त्व दिया जाता है।
- डस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में अक्सर बजिली खरीद, नयोजन और वनियमन के लयि अलग-अलग सेल होते हैं।
- ये अंतरसंबंधित गतिविधियाँ हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस सेलों के बीच समन्वय सीमति है।
- इस कमजोर व्यवस्था के कारण लंबी अवधि के बजिली खरीद संबंधी उत्तरदायित्वों में स्पष्टता का अभाव आ जाता है।
- संसाधन नयोजन त्रुटिपूरण प्रथाओं, लोड पूरवानुमान की खराब गुणवत्ता और राज्य सरकारों द्वारा कयि जाने वाले अत्यधिक हस्तक्षेप जैसे कई कारकों के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
- मौजूदा नयोजन प्रक्रयि में सबसे हैरान करने वाला पहलू कसि भी अनश्चितता की स्थिति संबंधी वशिलेषण और जोखमि प्रबंधन हेतु उपायों की घोर कमी है।
- करोड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी इस बारे में न सोचना, कयिदा भवषिय में सब कुछ अपेक्षानुसार घटति न हुआ तो क्या होगा, बेहद गैर-जमिमेदाराना और अतारककि प्रतीत होता है।

### आगे की राह

- अतः स्पष्ट तौर पर, बजिली खरीद प्रथाओं में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। अधिक उन्नत देशों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
- भारत में, प्रभावी संसाधन योजना का एक अतिरिक्त लाभ, बजिली आपूर्ति पर प्रति किलोवाट की लागत में कमी होगी।
- अधिकांश डस्टिकॉम वर्तमान में प्रभावी ढंग से संसाधनों के नयोजन में असमर्थ हैं, जसिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आगामी अधिक चुनौतीपूर्ण भवषिय हेतु पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इन्हें अपने संगठनात्मक ढाँचे में सुधार लाने होंगे।
- बजिली नयामक आयोगों को ऐसे वनियम वकिसति करने होंगे, जनिमें डस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्रभावी संसाधन योजनाओं के विकास के लयि उत्तरदायी बनाया जाए।
- संसाधन नयोजन में नयामक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता है।
- हालाँकि, इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि दीर्घकालिक बजिली खरीद प्रथाओं की खामियों को पहचाना जा रहा है।
- नीता आयोग के तीन-वर्षीय एक्शन एजेंडा (2017-18 से 2019-20) में कहा गया है कि 2019-20 के बाद कोई भी क्षमता वृद्धि बजिली की मांग और परचालन व्यवहार्यता के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिये।

